इकाई 14 वैश्वीकरण और विकास *

संरचना

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के सिद्धांत

14.2.1 पूर्ण लाभ का सिद्धांत

14.2.2 तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत

14.2.3 हेक्शर–ओहलिन प्रमेय

14.3 टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाएँ

14.3.1 टैरिफ बाधाएँ

14.3.2 गैर–टैरिफ बाधाएँ

14.4 बहुपक्षीय व्यापार समझौते

14.5 व्यापारिक गुट

14.5.1 एशिया–प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC)

14.5.2 यूरोपीय संघ

14.5.3 उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA)

14.5.4 आसियान (ASEAN)

14.5.5 सार्क (SAARC)

14.6 अंतर्राष्ट्रीय वित्त

14.6.1 अंतर्राष्ट्रीय वित्त का महत्व

14.6.2 वित्तीय वैश्वीकरण

14.7 सारांश

14.8 शब्दावली

14.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

* डॉ. निधि तेवतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठए इग्नू कृत

14.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य होंगे कि –

- मुक्त व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों को समझ सकें;
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ या उससे प्राप्ति की सराहना कर सकें;
- वैश्वीकरण के वर्तमान संदर्भ में समझाए गए सिद्धांतों की स्थिति को स्पष्ट कर सकें;
- टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाओं के बीच अंतर स्पष्ट कर सकें;
- गैट (GATT) और विश्व व्यापार संगठन के गठन और प्रगति की व्याख्या कर सकें;
- विभिन्न व्यापार समझौतों और व्यापार गुटों पर चर्चा कर सकें; तथा
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त तंत्र के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध कर सकें।

14.1 प्रस्तावना

इकाई का आरंभ मुक्त व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों के साथ होता है, यथा पूर्ण लाभ के सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत और हेक्शर–ओहलिन प्रमेय की व्याख्या। ये सिद्धांत बड़े देशों द्वारा छोटे देशों के शोषण के दायरे का भी संकेत देते हैं। व्यापार की रक्षा के लिए अनेक देश टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाएँ लगाते हैं, जो कि इन देशों को शोषण से बचने में मदद करता है। यहाँ ऐसी बाधाओं को विस्तार से समझाया गया है। इसके बाद इकाई विभिन्न व्यापार समझौतों का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ती है, यथा द्विपक्षीय समझौते, बहुपक्षीय समझौते और व्यापार गुट। यहाँ गैट (GATT) जैसे व्यापार समझौतों के उद्देश्यों और प्रगति के साथ–साथ विश्व व्यापार संगठन के गठन को भी समझाया गया है। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ते महत्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी संरचना की आवश्यकता और उसके लाभों को इकाई के अंत में विस्तार से समझाया गया है।

14.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के सिद्धांत

व्यापार सिद्धांतों की एक अच्छी समझ व्यापार नीति–निर्माण के क्षेत्र में अधिक महत्व रखती है, विशेष रूप से वैश्वीकरण और व्यापार उदारीकरण पर हाल के रुझानों और बहस के संदर्भ में। इन सिद्धांतों के मूल कार्य को समझना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। विभिन्न व्यापार सिद्धांतकारों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संभावित लाभ के विभिन्न निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डाला है और उन पर बल दिया है। इन सिद्धांतों की कुछ प्रमुख कमियों को समझना भी आवश्यक होता है, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के विचारों की तुलना कर उनमें अंतर करने में मदद करती हैं।

14.2.1 पूर्ण लाभ का सिद्धांत

एडम स्मिथ ने यह कोरा सच सामने रखते हुए शुरुआत की कि दो राष्ट्रों के लिए स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए दोनों राष्ट्रों को लाभ होना चाहिए। यदि एक राष्ट्र को कुछ नहीं मिला या हानि झेलनी पड़ी तो वह व्यापार करने से इंकार कर देगा।

उसके अनुसार, दो राष्ट्रों के बीच व्यापार पूर्ण लाभ पर आधारित होता है। पूर्ण लाभ या निरपेक्ष लाभ के इस सिद्धांत को एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। चलिए, हम दो वस्तुओं A और B और दो राष्ट्रों X और Y का उदाहरण लेते हैं। मान लें कि वस्तु A और वस्तु B को अकेले श्रम द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। राष्ट्र X में वस्तु A की एक इकाई का निर्माण करने में श्रम की 10 इकाइयाँ लगती हैं जबकि राष्ट्र Y को इसी वस्तु के निर्माण में 20 श्रम इकाइयाँ लगती हैं। इसके विपरीत, राष्ट्र X में वस्तु B की एक इकाई के निर्माण में श्रम की 20 इकाइयाँ लगती हैं जबकि राष्ट्र Y को इसी वस्तु के निर्माण में 10 श्रम इकाइयाँ लगती हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्र X वस्तु A का उत्पादन करने में अधिक दक्ष है क्योंकि यह राष्ट्र Y की तुलना में उत्पादन की प्रति इकाई कम श्रम का प्रयोग करता है। इसी प्रकार, राष्ट्र Y वस्तु B के उत्पादन में अधिक दक्ष है। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्र X को वस्तु A के उत्पादन में राष्ट्र Y पर पूर्ण लाभ होता है और राष्ट्र Y को वस्तु B के उत्पादन में राष्ट्र X पर पूर्ण लाभ होता है।

ऐसी स्थिति में यदि प्रत्येक राष्ट्र अपने पूर्ण लाभ की वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है और फिर दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करता है तो दोनों राष्ट्रों को लाभ होगा। आइए, देखें कैसे। राष्ट्र Y वस्तु B की एक इकाई का उत्पादन करके, 10 श्रम इकाइयों का प्रयोग करके और राष्ट्र X को वस्तु A की एक इकाई के बदले निर्यात करके लाभ प्राप्त कर सकता है। वास्तव में, राष्ट्र Y ने 10 श्रम इकाइयों का ही प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु A की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए किया है, न कि इतने श्रम का प्रयोग करके सीधे वस्तु A की 0.5 इकाई का उत्पादन करने के लिए। इसी प्रकार, राष्ट्र X ने निर्यात के लिए वस्तु A की इकाई का उत्पादन करने के लिए श्रम की 10 इकाइयों का प्रयोग किया होगा, जिसके बदले उसे वस्तु B की एक इकाई प्राप्त हुई। किंतु यदि उसने वस्तु B की एक इकाई का उत्पादन करने का प्रयास स्वयं करता तो उसे श्रम की 20 इकाइयों की आवश्यकता होती। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यापार करके दोनों देशों को दोनों वस्तुओं के अधिक होने से लाभ होगा।

राष्ट्र यदि पूर्ण लाभ के सिद्धांत का पालन करते हैं तो उन्हें अवश्य लाभ होता है, तिस पर भी माल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ को पूर्ण लाभ की स्थितियों तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। डेविड रिकार्डो दर्शाते हैं कि तुलनात्मक लाभ की स्थितियों में भी व्यापार से लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

14.2.2 तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत

वर्ष 1817 में रिकार्डो ने अपनी पुस्तक *प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन* प्रकाशित की, जिसमें तुलनात्मक लाभ का नियम प्रस्तुत किया गया था। इस नियम के अनुसार, भले ही एक राष्ट्र दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे राष्ट्र की तुलना में कम दक्ष हो (जिसके संबंध में पूर्ण नुकसान होता है), फिर भी पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार के लिए एक आधार है। आइए, इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें।

मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में केवल दो व्यक्ति ब्रैड और क्लेयर हैं तथा वे खाद्य और लकड़ी का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का दैनिक उत्पादन तालिका 14.1 में

दिया गया है। यह स्पष्ट है कि क्लेयर को खाद्य और लकड़ी दोनों के उत्पादन में पूर्ण लाभ है क्योंकि वह ब्रैड की तुलना में एक ही समय में दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन करती है। अब प्रश्न यह है कि तब ब्रैड क्या उत्पादन करे और क्या दोनों व्यक्तियों को व्यापार से लाभ होगा? वास्तव में, यदि इस स्तर पर तुलनात्मक लाभ में प्रकट अवसर लागत की अवधारणाओं को समझ लिया जाए तो क्लेयर और ब्रैड दोनों को व्यापार से लाभ होगा। सरल शब्दों में, किसी वस्तु A की अवसर लागत को किसी अन्य वस्तु, यथा वस्तु B, की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे वस्तु A की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है।

तालिका 14.1: खाद्य और लकड़ी का दैनिक उत्पादन

	खाद्य (बुशल में)	लकड़ी (लट्ठों में)
ब्रैड	16	8
क्लेयर	20	20

ब्रैड एक दिन के काम में लकड़ी के 8 लट्ठे या 16 बुशल खाद्य का उत्पादन करता है। इस 16 बुशल खाद्य का उत्पादन करने के लिए ब्रैड को लकड़ी के 8 लट्ठे छोड़ देने होंगे। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में 1 लट्ठा लकड़ी की हानि होती है और 2 बुशल खाद्य का लाभ होता है।

यहाँ लकड़ी के 1 लट्ठे की अवसर लागत 2 बुशल खाद्य है। दूसरी ओर, 1 बुशल खाद्य की अवसर लागत लकड़ी का आधा लट्ठा है। क्लेयर एक ही दिन में 20 लट्ठे लकड़ी या 20 बुशल खाद्य का उत्पादन करती है। उसके मामले में, उसे 20 बुशल खाद्य का उत्पादन करने के लिए 20 लट्ठे लकड़ी छोड़नी होगी। तदनुसार, अर्थव्यवस्था में 1 लट्ठा लकड़ी की हानि होगी और 1 बुशल खाद्य का लाभ होगा।

इसका अर्थ है कि 1 लट्ठा लकड़ी की अवसर लागत 1 बुशल खाद्य है और इसका विपरीत भी सत्य है। अतएव, यदि हम दोनों व्यक्तियों के मामले में एक समान हानि रखते हैं अर्थात् यदि प्रत्येक को 1 लट्ठा लकड़ी छोड़ने के लिए कहा जाता है तो क्लेयर 1 बुशल खाद्य का उत्पादन करती है जबकि ब्रैड 2 बुशल खाद्य का उत्पादन करता है। खाद्य का उत्पादन करने वाले ब्रैड के मामले में लाभ अधिक है।

इस मामले में अवसर लागत कम है, जिसका अर्थ यह भी है कि ब्रैड खाद्य के उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक दक्ष है। अतः ब्रैड खाद्य का ही उत्पादन करेगा। रिकार्डो के अनुसार, ब्रैड को भोजन के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है। इसी प्रकार, यदि हम प्रत्येक को 1 बुशल खाद्य छोड़ने और लकड़ी के लट्ठे का उत्पादन शुरू करने के लिए कहें तो ब्रैड लकड़ी का आधा लट्ठा और क्लेयर 1 लट्ठा लकड़ी का उत्पादन करती है। यह इंगित करता है कि क्लेयर को लकड़ी के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है।

अतः क्लेयर को लकड़ी का ही उत्पादन करना चाहिए और ब्रैड को खाद्य का ही उत्पादन करना चाहिए। दोनों व्यक्तियों को तुलनात्मक लाभ की वस्तु दूसरे को बेच देनी चाहिए। यही बात देशों और व्यापार पर भी लागू होती है। यदि किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर

लागत एक देश में दूसरे देश की तुलना में कम हो तो उस देश को उस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है।

14.2.3 हेक्शर–ओहलिन प्रमेय

विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न देशों के पास भिन्न–भिन्न बन्दोबस्ती कारक और प्रौद्योगिकी होते हैं। हेक्शर–ओहलिन (H-O) प्रमेय से ज्ञात होता है कि तुलनात्मक लाभ राष्ट्रों के संसाधनों और उत्पादन प्रौद्योगिकी के बीच अंतर्क्रिया से प्रभावित होता है। उत्पादन के कुछ कारक दुर्लभ हैं तो कुछ किसी ज्ञात राष्ट्र के पास बहुतायत में हैं। इसी प्रकार, प्रौद्योगिकी यह निर्धारित करती है कि विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं को तय करते समय किसी राष्ट्र को किस स्तर के तीव्रता गुणांक पर संचालित होना है।

हेक्शर–ओहलिन (H-O) मॉडल की कल्पना सबसे पहले दो स्वीडिश अर्थशास्त्रियों ने की थी, यथा एली हेक्शर और बर्टिल ओहलिन। इस मॉडल के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार उन देशों के सापेक्ष बंदोबस्ती कारकों में अंतर के कारण होता है। यह दीर्घकालिक सामान्य साम्यावस्था का सिद्धांत है, जिसमें दो कारक व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच गतिशील रहते हैं। तदनुसार, H-O प्राधार 'कारक अनुपात' के संदर्भ में व्यापार के निर्धारक तत्वों पर नया प्रकाश डालता है और इसे 'कारक–अनुपात सिद्धांत' के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कारक का दूसरे कारक से अनुपात (या समानुपात) होता है, जो कि मॉडल को उसका सामान्य नाम देता है – कारक–अनुपात मॉडल।

इस सिद्धांत के अनुसार, व्यापार के निर्धारक तत्व देशों के बंदोबस्ती कारक और माल के तीव्रता गुणांक होते हैं। कोई देश उस वस्तु में विशेषज्ञता प्राप्त करता है और उसका निर्यात करता है जिसमें वह अपने सबसे प्रचुर कारक का गहनता से प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत जैसा किसी देश में श्रम प्रचुर मात्रा में है तो देश मुख्य रूप से श्रम–गहन वस्तुओं में विशेषज्ञ होगा, जो कि उसके निर्यात टोकरी का एक बड़ा हिस्सा होंगी। दूसरी ओर, भारत उन देशों से पूँजी–गहन वस्तुओं का आयात करेगा जहाँ पूँजी प्रचुर मात्रा में हैं।

उक्त (H-O) मॉडल में पूँजी की मात्रा और उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त श्रम की मात्रा का अनुपात पूँजी–श्रम (K/L) अनुपात होता है। साथ ही, यह माना जाता है कि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले विभिन्न उद्योगों में अलग–अलग पूँजी–श्रम अनुपात होता हैं। एक उद्योग जिसमें दूसरे उद्योग की तुलना में उच्च ज्ञध्स् अनुपात होता है, वह दूसरे की तुलना में पूँजी–गहन उद्योग होता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि दूसरा उद्योग पहले उद्योग की तुलना में श्रम प्रधान है।

अमेरिका जैसे कुछ देश अपनी श्रम शक्ति के सापेक्ष भौतिक पूँजी से संपन्न हैं। इसके विपरीत, कई अल्प विकसित देशों के पास बहुत कम भौतिक पूँजी है, परंतु वे बड़ी श्रम शक्ति से संपन्न हैं। विभिन्न देशों के बीच सापेक्ष कारक प्रचुरता को परिभाषित करने के लिए श्रम की कुल बंदोबस्ती के प्रति पूँजी की कुल बंदोबस्ती के अनुपात का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि अमेरिका के पास श्रम की प्रति इकाई कुल पूँजी अनुपात भारत के पास श्रम की प्रति इकाई कुल पूँजी अनुपात की तुलना में बड़ा हो

तो हम कहेंगे कि अमेरिका भारत के सापेक्ष पूँजी–प्रचुर है। यहाँ निहितार्थ से भारत के पास पूँजी की प्रति इकाई कुल श्रम का एक बड़ा अनुपात होगा और इस प्रकार भारत अमेरिका के सापेक्ष श्रम–प्रचुर होगा।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, H-O प्रमेय के अनुसार एक पूँजी–प्रचुर देश पूँजी–गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा जबकि एक श्रम–प्रचुर देश श्रम–गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा। पूँजी–प्रचुर वह देश होता है जो किसी दूसरे देश के सापेक्ष पूँजी से संपन्न होता है। यह देश को उस वस्तु का उत्पादन करने की प्रवृत्ति प्रदान करता है जो उत्पादन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक पूँजी का प्रयोग करती है, यथा पूँजी–गहन वस्तु। परिणामतः यदि ये दोनों देश शुरू में व्यापार नहीं कर रहे थे अर्थात् वे निरंकुश थे तो पूँजी–प्रचुर देश में पूँजी–गहन वस्तु की कीमत दूसरे देश में उस वस्तु की कीमत के सापेक्ष (उसकी अतिरिक्त आपूर्ति के कारण) नीचे चली जाएगी।

इसी प्रकार, श्रम–प्रचुर देश में श्रम–गहन वस्तु की कीमत पूँजी–प्रचुर देश में उस वस्तु की कीमत के सापेक्ष नीचे चली जाएगी। उसी तरीके से, पूँजी–प्रचुर देश में श्रम–गहन सामान महँगा होगा और श्रम–प्रचुर देश में पूँजी–गहन सामान ऊँची कीमत पर उपलब्ध होगा।

एक बार व्यापार की अनुमति मिल जाने के बाद लाभ चाहने वाली कंपनियाँ अपने उत्पादों को उन बाजारों में स्थानांतरित कर देती हैं जहाँ उनकी कीमत अस्थायी रूप से अधिक हो। इस प्रकार, पूँजी–प्रचुर देश पूँजी–गहन माल का निर्यात करेगा क्योंकि उसके माल की कीमत दूसरे देश में अस्थायी रूप से अधिक होगी। इसी प्रकार, श्रम–प्रचुर देश श्रम–गहन वस्तु का निर्यात करेगा। यह व्यापार प्रवाह तब तक बढ़ता रहेगा जब कि तक दोनों बाजारों में दोनों वस्तुओं की कीमतें बराबर न हो जाए।

14.3 टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाएँ

व्यापार सुरक्षा के लिए अनेक उपकरण या उपाय अपनाए जाते हैं। व्यापार सुरक्षा के उपकरण जो देश आमतौर पर आयात को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयोग करते हैं, मोटे तौर पर मूल्य संबंधी मापदंडों और गैर–मूल्य मापदंडों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, यथा टैरिफ बाधाएँ (tariff barriers) और गैर–टैरिफ बाधाएँ (NTBs)।

14.3.1 टैरिफ बाधाएँ

टैरिफ अर्थात् सीमा–शुल्क एक प्रकार का कर है, जो कि किसी वस्तु का आयात किए जाने पर वसूला जाता है। यह कर तैयार माल और मध्यवर्ती माल दोनों के आयात पर लागू किया जा सकता है। टैरिफ विशिष्ट अथवा यथामूल्य हो सकते हैं। विशिष्ट टैरिफ माल की प्रति इकाई एक निश्चित राशि के रूप में लगाए जाते हैं (उदाहरण के लिए, आयातित खजूर का 400 रुपये प्रति बॉक्स), जबकि यथामूल्य टैरिफ माल के कुल मूल्य के एक नियत प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है (उदाहरण के लिए, आयातित कंप्यूटर पार्ट्स पर 30 प्रतिशत शुल्क)। टैरिफ व्यापार नीति का सबसे पुराना रूप है और पारंपरिक रूप से सरकारी आय के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। टैरिफ चाहे तैयार माल पर लगाया जाए या फिर मध्यवर्ती माल पर, इसके प्रभाव से किसी देश को भेजे जाने वाले माल की लागत बढ़ जाती है। माल भेजने वाले किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण से टैरिफ

परिवहन लागत की भाँति होता है। यदि देश A आयातित गेहूँ के प्रत्येक बुशल पर 100 रुपये का कर लगाता हो तो पोतवणिक (shippers) गेहूँ को स्थानांतरित करने के लिए तब तक तैयार नहीं होंगे जब तक कि दोनों बाजारों के बीच मूल्य अंतर कम से कम 100 रुपये न हो।

किसी भी आयातित वस्तु पर टैरिफ उस वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्राप्त मूल्य को बढ़ा देता है। यही प्रभाव प्रायः टैरिफ का मुख्य उद्देश्य होता है, यथा घरेलू उत्पादकों को उन कम कीमतों से बचाना जो आयात प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होंगी। इन मूल्य परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को आयातक देश में हानि होती है और निर्यातक देश में लाभ मिलता है। इसके विपरीत, उत्पादकों को आयातक देश में लाभ होता है और निर्यातक देश में हानि होती है। इसके अलावा, टैरिफ या आयात–शुल्क घरेलू बाजार में गैर–व्यापारिक वस्तुओं की तुलना में व्यापारिक वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में अनिवार्यतः हेर–फेर करता है।

व्यवहारतः व्यापार नीति का विश्लेषण करने में यह पूछना आवश्यक होता है कि टैरिफ या कोई अन्य व्यापार नीति वास्तव में कितनी सुरक्षा, यथा 'संरक्षण की प्रभावी दर' प्रदान करती है, जिसका उपयोग संपूर्ण टैरिफ संरचना (तैयार और मध्यवर्ती माल को शामिल करते हुए) द्वारा किसी उद्योग विशेष में मूल्य–वर्धित कीमत को दी गई वास्तविक सुरक्षा की सीमा को मापने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर आमतौर पर उस मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जो मुक्त व्यापार के तहत अभिभावी होगा। उदाहरण के लिए, चीनी पर कोई आयात नियतांश (quota) अमेरिकी चीनी उत्पादकों द्वारा प्राप्त मूल्य को 35 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।

किसी टैरिफ के मामले में सुरक्षा को मापना सीधा प्रतीत होता है, यथा यदि टैरिफ आयात मूल्य के मूल्यानुसार कर हो तो टैरिफ दर स्वयं ही सुरक्षा की मात्रा को माप देगीय यदि टैरिफ विशिष्ट हो तो टैरिफ को टैरिफ के निवल मूल्य से विभाजित करने पर हमें यथामूल्य समकक्ष प्राप्त होता है। बहरहाल, इतनी सरलता से सुरक्षा की दर परिकलित करने के प्रयास में दो समस्याएँ आती हैं।

प्रथम, यदि आपका अनुमान पूर्णतः सही न हो कि देश का आयात विश्व बाजार का एक बहुत छोटा–सा हिस्सा है तो टैरिफ के एक प्रभाव स्वरूप घरेलू कीमतें बढ़ने की बजाय विदेशी निर्यात मूल्य कम हो जाएँगे। विदेशी निर्यात मूल्यों पर व्यापार नीतियों का यह प्रभाव कभी–कभी महत्वपूर्ण होता है।

दूसरी समस्या यह है कि किसी वस्तु के उत्पादन के विभिन्न चरणों पर टैरिफ का बहुत भिन्न प्रभाव हो सकता है।

आधुनिक समय में टैरिफ के महत्व में गिरावट आई है क्योंकि आधुनिक सरकारें आमतौर पर विभिन्न प्रकार के गैर–टैरिफ बाधाओं (जिन पर अगले पाठांश में चर्चा की गई है) के माध्यम से घरेलू उद्योगों की रक्षा करना पसंद करती हैं। तिस पर भी अन्य व्यापार नीतियों को समझने के लिए टैरिफ के प्रभावों की समझ आवश्यक है।

14.3.2 गैर–टैरिफ बाधाएँ

टैरिफ बाधाएँ सबसे सरल व्यापार नीतियाँ हैं, परंतु आधुनिक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिकांश सरकारी हस्तक्षेप अन्य रूप ले लेता है, जिन्हें गैर–टैरिफ बाधाओं (NTBs) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये बाधाएँ (NTBs) व्यापारिक वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा व अन्य विशेषताओं पर लागू होती हैं। टैरिफ बाधाओं के विपरीत, गैर–टैरिफ बाधाएँ आयातित वस्तुओं के प्रवाह पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगा सकती हैं। उदाहरण के लिए, आयात नियतांश जैसी पारंपरिक गैर–टैरिफ बाधाएँ घरेलू देश में आयात की मात्रा को सीधे सीमित कर देती हैं। जबकि अन्य गैर–टैरिफ बाधाएँ व्यापारिक वस्तुओं के प्रवाह को अधिक अप्रत्यक्ष तरीके से प्रतिबंधित करती हैं।

आयात नियतांश : किसी देश में आयात नियतांश (import quota) उसके आयात की मात्रा पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाता है। व्यवहारतः नियतांश किसी आयात लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है। केवल लाइसेंस धारकों को ही घरेलू बाजार में आयातित माल की निर्दिष्ट मात्रा में आयात करने की अनुमति दी जाती है। इस मिथ्या धारणा होने से बचना आवश्यक है कि आयात नियतांश किसी प्रकार घरेलू कीमतों को बढ़ाए बिना आयात को सीमित कर देता है। सच्चाई यह है कि कोई भी आयात नियतांश हमेशा आयातित वस्तु की घरेलू कीमत को बढ़ाता है।

जब आयात सीमित होता है तो तत्काल परिणाम यह होता है कि प्रारंभिक कीमत पर वस्तु की माँग घरेलू आपूर्ति और आयात से अधिक हो जाती है। इससे बाजार समाशोधन होने तक कीमत की बोली लगाई जाती रहती है। अंततः कोई भी आयात नियतांश घरेलू कीमतों को किसी टैरिफ के रूप में उसी स्तर तक बढ़ा देगा जहाँ आयात समान स्तर तक सीमित हो जाता है। नियतांश और टैरिफ के बीच अंतर यही है कि नियतांश से सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है।

जब आयात को प्रतिबंधित करने के लिए टैरिफ की बजाय नियतांश का उपयोग किया जाता है तो वह राशि जो टैरिफ के साथ सरकारी राजस्व के रूप में दिखाई देती है, लाइसेंस धारक द्वारा एकत्र कर ली जाती है। इस प्रकार, आयात लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यापारी आयातित माल को खरीदने और उसे घरेलू बाजार में ऊँची कीमत पर फिर से बेच देने में सक्षम होता है। आयात लाइसेंस धारकों द्वारा प्राप्त लाभ नियतांश किराया (quota rent) कहलाता है।

निर्यात अनुदान : निर्यात अनुदान (export subsidy) उस फर्म या व्यक्ति को किया गया भुगतान है जो विदेशों को माल का नौभार प्रेषण करता है। किसी टैरिफ की भाँति निर्यात अनुदान या तो विशिष्ट (प्रति यूनिट एक नियत राशि) अथवा यथामूल्य (निर्यात मूल्य के अनुपात में) हो सकती है। जब सरकार किसी निर्यात अनुदान का प्रस्ताव करती है तो पोतवणिक उस बिंदु तक माल का निर्यात करेंगे जहाँ घरेलू कीमत विदेशी मूल्य से बढ़कर अनुदान राशि तक अधिक हो जाती है।

स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध : आयात नियतांश का एक भिन्नरूप स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध (VER) है, जिसे स्वैच्छिक संयम समझौता (VRA) भी कहा जाता है। स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध व्यापार पर आयातक देश की बजाय निर्यातक देश की ओर से अध्यारोपित एक

नियतांश होता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वर्ष 1981 के बाद जापान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को कार निर्यात पर लागू सीमा है। बहरहाल, आर्थिक दृष्टिकोण से स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध एक आयात नियतांश की भाँति होता है जहाँ लाइसेंस विदेशी सरकारों को सौंपे जाते हैं और इस कारण यह आयातक देश के लिए बहुत महँगा होता है।

वस्तुतः आयातक देश के लिए स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध उस टैरिफ की तुलना में हमेशा अधिक महँगा पड़ता है जो समान राशि से आयात को सीमित करता है। इनमें अंतर यह होता है कि टैरिफ के तहत जो राजस्व कहलाता वह स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध के तहत विदेशियों द्वारा अर्जित किराया बन जाता है, जिससे ये प्रतिबंध (VER) स्पष्ट रूप से आयातक देश के लिए हानि उपगत करते है। इसका अर्थ है कि स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध निर्यातक देश के लिए लाभकारी और आयातक देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

स्थानीय सामग्री आवश्यकता : स्थानीय सामग्री आवश्यकता (LCR) एक ऐसा विनियमन है जिसके लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले तैयार माल के कुछ निर्दिष्ट अंश की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में यह अंश भौतिक इकाइयों में निर्दिष्ट होता है। अन्य मामलों में आवश्यकता को मूल्य के संदर्भ में इस अपेक्षा के साथ कहा जाता है कि माल की कीमत का कुछ न्यूनतम हिस्सा वर्धित घरेलू मूल्य को निरूपित करेगा।

विकासशील देशों द्वारा स्थानीय सामग्री विनियमों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता रहा है, जो कि अपने विनिर्माण आधार को समन्वायोजन (assembling) से वापस मध्यवर्ती माल में स्थानांतरित करने का प्रयास करते रहे हैं। समन्वायोजन हेतु विभिन्न कलपुर्जों के घरेलू उत्पादकों के दृष्टिकोण से स्थानीय सामग्री विनियमन उसी प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है जैसे कि कोई आयात नियतांश करता है।

उन फर्मों के दृष्टिकोण से जिन्हें स्थानीय रूप से ही खरीददारी करनी चाहिए, बहरहाल, इसके प्रभाव कुछ भिन्न होते हैं। स्थानीय सामग्री आयात की कोई कठोर सीमा नहीं रखती है। इसकी बजाय यह फर्मों को अधिक आयात करने की अनुमति देती है, बशर्ते वे घरेलू स्तर पर भी अधिक खरीददारी करें। इसका अर्थ यह है कि फर्म के लिए आगत की प्रभावी कीमत आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित आगत की कीमत का औसत होती है।

विनिमय नियंत्रण : विनिमय नियंत्रण (exchange controls) देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध होते हैं, जो कि घरेलू निवासियों की घरेलू मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की क्षमता को सीधे सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए, विनिमय नियंत्रण लागू करने का वह तरीका जिसमें विदेशी मुद्रा बैंक खाते रखने के लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति प्राप्त करना शामिल होता है।

आयात जमा योजनाएँ : ये योजनाएँ (import deposit schemes) देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा लागू किए गए ऐसे नियम होती हैं जो आयात को और अधिक महँगा बनाकर प्रतिबंधित करती हैं। उदाहरण के लिए, नियमों के तहत आयातकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित राशि (आमतौर पर आयातित माल के मूल्य के अनुपात में) जमा करने की आवश्यकता होती है, जिससे आयात की लागत प्रभावी रूप से बढ़ जाती है।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 1

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।
ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपनी प्रगति की जाँच करें।

1) पूर्ण लाभ के सिद्धांत को किसी उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

2) किसी देश को तुलनात्मक लाभ किस प्रकार व्यापार में सहायता करता है? सोदाहरण स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

3) कौन–सा सिद्धांत व्यापार के आधार को बंदोबस्ती कारक और तीव्रता गुणांक के रूप में बताता है? सिद्धांत की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

4) व्यापार बाधा के रूप में टैरिफ पर चर्चा करें और उसकी जाँच करें। टैरिफ लगाने वाले देश को इससे क्या लाभ होते हैं?

.....

.....

.....

14.4 बहुपक्षीय व्यापार समझौते

व्यापार नीति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित टैरिफ में कमी की शुरुआत सन 1930 के दशक में तब हुई जब अमेरिका ने स्मूट–हॉली अधिनियम पारित किया। उसके बाद से व्यापार समझौतों के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है।

द्विपक्षीय वार्ताएँ, बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का पूरा लाभ नहीं उठाती हैं। किसी द्विपक्षीय वार्ता से लाभ उन पक्षों तक भी ''छलक'' सकते है जिन्होंने कभी कोई रियायत दी ही न हो। उदाहरण के लिए, यदि ब्राजील के साथ किसी समझौते के परिणामस्वरूप अमेरिका कॉफी पर टैरिफ कम करता है तो कोलंबिया को भी विश्व कॉफी की ऊँची कीमत से लाभ होगा।

इसके अलावा, कुछ लाभकारी सौदों में स्वाभाविक रूप से दो से अधिक भागीदार शामिल हो सकते हैं, यथा संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप को अधिक माल बेचता है, यूरोप सऊदी अरब को अधिक माल बेचता है, सऊदी अरब जापान को अधिक माल बेचता है और जापान संयुक्त राज्य अमेरिका को अधिक माल बेचता है। तदनुसार, द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उदारीकरण में अगला कदम कई देशों को शामिल करते हुए बहुपक्षीय वार्ताओं को आगे बढ़ाना ही रहा।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद बहुपक्षीय वार्ता शुरू हुई। इसमें 23 देशों के एक समूह ने अपनी अनंतिम नियमावली के तहत व्यापार वार्ता शुरू की, जिसे प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता या गैट (GATT) नाम दिया गया। यह अनंतिम समझौता ही अगले 48 वर्षों तक विश्व व्यापार को नियंत्रित करता रहा।

गैट में भाग लेने वाले देशों को आधिकारिक तौर पर अनुबंधित पक्षों के रूप में नामित किया गया था। तदंतर वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना की गई, जो कि अंतिम रूप से गठित औपचारिक संगठन माना गया। बहरहाल, वही गैट नियम लागू हैं और व्यवस्था का मूल तर्क वही बना हुआ है। संगठन का पुनः पतन रोकने के लिए अनुबंधन की प्रक्रिया अस्तित्व में है। इसमें बाउंड टैरिफ दर का अर्थ है कि टैरिफ लगाने वाला देश भविष्य में दर न बढ़ाने के लिए सहमत है। यहाँ बाउंड टैरिफ के अलावा गैट–विश्व व्यापार संगठन (GATT-WTO) प्रणाली भी आमतौर पर व्यापार में गैर–टैरिफ हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास करती है।

आगे बढ़ने के लिए एक शैलीबद्ध प्रक्रिया भी अस्तित्व में है, जिसे व्यापार दौर (trade round) के रूप में जाना जाता है। इसमें देशों का एक बड़ा समूह व्यापार को उदार बनाने के लिए टैरिफ कटौती व अन्य उपायों की किसी श्रृंखला पर बातचीत करने के लिए एक स्थान पर एकत्र होता है। वर्ष 1947 के बाद से आठ व्यापार दौर पूरे हो चुके हैं। गैट के तहत पहले पाँच व्यापार दौरों ने समानांतर द्विपक्षीय वार्ता का रूप ले लिया, जहाँ प्रत्येक देश एक साथ कई देशों के साथ युग्मानुसार बातचीत करता है।

बहुपक्षीय समझौते सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई भी देश एक देश को दूसरे देश से बेहतर व्यापार सौदे नहीं दे सकता। इससै खेल का मैदान समतल होता है। यह उभरते बाजार वाले देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनमें से कई देश आकार में छोटे हैं, जो कि उन्हें कम प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। यह प्रत्येक भागीदार के लिए व्यापार में वृद्धि करता है। उनकी कंपनियाँ कम टैरिफ का लाभ उठाती हैं।

इससे उनका निर्यात सस्ता हो जाता है। यह सभी व्यापार भागीदारों के लिए वाणिज्य नियमों का मानकीकरण करता है। इससे कंपनियों की कानूनी लागत कम होती है क्योंकि वे प्रत्येक देश के लिए समान नियमों का पालन करती हैं। इसके अलावा, देश एक समय में एक से अधिक देशों के साथ व्यापार सौदों पर बातचीत कर सकते हैं।

14.5 व्यापारिक गुट

जैकब वाइनर ने सीमा–शुल्क संघों के सिद्धांत संबंधी अपने अग्रणी अध्ययन में व्यापार सृजन और व्यापार पथांतरण की प्रमुख अवधारणाएँ प्रस्तुत कीं। एक सरल मॉडल के

माध्यम से विनर ने दर्शाया कि एक सीमा–शुल्क संघ गठित करने से अनेक कल्याणकारी प्रभाव हो सकते हैं, जबकि अन्य परिस्थितियों में कल्याण–ह्रासकारी प्रभाव हो सकते हैं।

व्यापार सृजन (trade creation) का अर्थ होता है कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) अधिमान्य टैरिफ रियायतों के माध्यम से ऐसा व्यापार उत्पन्न करता है जो अन्यथा अस्तित्व में नहीं होता। परिणामतः इस क्षेत्र (FTA) के भीतर उत्पाद के पहले से अधिक कुशल उत्पादक की ओर से आपूर्ति होने लगती है। सभी मामलों में व्यापार सृजन देश के राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ाएगा क्योंकि आयात के स्थान पर उच्च लागत वाला घरेलू उत्पादन होने लगेगा।

दूसरी ओर, व्यापार पथांतरण (trade diversion) का अर्थ होता है कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) अपने क्षेत्र से बाहर किसी अधिक कुशल आपूर्तिकर्ता से दूर चल रहे व्यापार को इस क्षेत्र (FTA) के भीतर ही किसी कम कुशल आपूर्तिकर्ता की ओर मोड़ देता है। कुछ मामलों में व्यापार पथांतरण देश के राष्ट्रीय कल्याण को कम कर देगा, परंतु कुछ अन्य मामलों में व्यापार पथांतरण के बावजूद राष्ट्रीय कल्याण में सुधार हो सकता है। यदि व्यापार सृजन का सकारात्मक प्रभाव व्यापार पथांतरण के नकारात्मक प्रभावों से बड़ा हो तो यह क्षेत्र (FTA) राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि करेगा।

यही कारण है कि तत्कालीन गैट और वर्तमान विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय व्यवस्था भी सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) में निहित गैर–भेदभाव के सिद्धांत के अल्पीकरण की अनुमति देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही विश्व व्यापार संगठन के अधिकांश सदस्य एक या एक से अधिक क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के पक्षकार हैं। परिणामतः वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTAs) के तहत किया जाता है, न कि सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत के तहत।

इसी कारण क्षेत्रीय व्यापारिक गुट वैश्विक व्यापार के प्रवर्तक के रूप में उभरे हैं। फिर भी यदि कोई समझौता (RTA) व्यापार सृजन के सकारात्मक प्रभावों की तुलना में व्यापार पथांतरण के अधिक नकारात्मक प्रभावों का कारण बनता है तो वह समझौता (RTA) किसी देश के लिए कल्याण–ह्रासकारी हो सकता है।

14.5.1 एशिया–प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC)

एपेक (APEC) ने वर्ष 1989 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में 12 सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय संवाद समूह के रूप में शुरुआत की। एपेक आर्थिक नेताओं ने एशिया–प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के दृष्टिकोण ''अपने लोगों के लिए स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि'' को रेखांकित करने के लिए पहली बार वर्ष 1993 में अमेरिका में सभा की।

वर्ष 2000 में ब्रुनेई में एपेक ने व्यक्तिगत कार्य योजना (IAP) ऑनलाइन प्रदान करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक व्यक्तिगत कार्य योजना (e-IAP) प्रणाली की स्थापना की और नई अर्थव्यवस्था हेतु कार्य योजना के प्रति वचनबद्ध हो गया, जिसका लक्ष्य अन्य उद्देश्यों के साथ वर्ष 2005 तक पूरे एपेक क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग तिगुना कर देने का तय किया गया।

इसने विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास एजेंडा वार्ता को फिर से सक्रिय करने के लिए सहमति व्यक्त की तथा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के अनुपूरक उद्देश्यों पर बल दिया। एपेक ने स्वयं को न केवल सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रति, बल्कि एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा में सुधार के प्रति भी समर्पित किया। एपेक ने आतंकवादी समूहों को नष्ट करने, सामूहिक विनाश के हथियारों के खतरे को खत्म करने और अन्य सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई करने का वचन दिया।

एपेक ने ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण, सुदृढ़ एवं कार्यक्षम वित्तीय प्रणालियों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संरचनात्मक सुधार में तेजी लाने के अपने प्रयासों को भी सशक्त किया। विश्व नेताओं ने चीन के हांगकांग शहर में विश्व व्यापार संगठन की छठी मंत्रिस्तरीय बैठक के सफल निष्कर्ष के समर्थन में एक स्वाश्रयी बयान जारी किया और सर्वव्यापी स्वास्थ्य खतरों का सामना करने और वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए सहमत हुए, जो कि इस क्षेत्र के लिए गहरी आर्थिक असुरक्षा का कारण बन सकता है।

14.5.2 यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) से विकसित हुआ, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में छह संस्थापक सदस्यों द्वारा की गई थी, जो थे – बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग (बेनेलक्स देश), पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और इटली। इसका उद्देश्य सदस्य राज्यों के इस्पात और कोयला संसाधनों को साझा करना था, ताकि कोई और यूरोपीय युद्ध रोका जा सके। उक्त समुदाय (ECSC) के बाद एक यूरोपीय रक्षा समुदाय (EDC) और एक यूरोपीय राजनीतिक समुदाय (EPC) को स्थापित करने का प्रयास किया गया।

उक्त दोनों समुदायों (EDC और EPC) की विफलता के बाद इन छह संस्थापक सदस्यों ने अपने एकीकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश की और यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) की स्थापना की। इस समुदाय (EEC) का उद्देश्य ''चार स्वतंत्रताओं'' के आधार पर उक्त छह संस्थापक सदस्यों के बीच एक सीमा–शुल्क संघ स्थापित करना था, यथा माल, सेवाओं, पूँजी और लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता।

इन यूरोपीय समुदायों के विकास को वर्तमान में यूरोपीय संघ में दो समानांतर प्रक्रियाओं से युक्त कहा जा सकता है – पहले उनका संरचनात्मक क्रमविकास और फिर राष्ट्रोपरि स्तर को दी गई अधिक क्षमता के साथ एक अधिक चुस्त गुट के रूप में संस्थागत परिवर्तन, जिसे 'यूरोपीय एकीकरण' अथवा संघ के गहनन की प्रक्रिया कहा जा सकता है। यूरोपीय समुदायों (और बाद में यूरोपीय संघ) का विस्तार 6 से 25 सदस्य राज्यों के रूप में हुआ, जिसे 'संघ का विस्तार' भी कहा जाता है।

तदंतर 1 जनवरी 2002 को यूरो के नोट और सिक्के प्रचलन में आए। यूरोपीय संघ (EU) को किसी सीमा–शुल्क संघ और एक मौद्रिक एवं आर्थिक संघ का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण माना जाता है। बहरहाल, इसके सदस्यों के बीच मतभेदों के कारण कुछ समस्याएँ आगे आई हैं, जैसे कि यूरो के मामले में, जिसको पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं है।

14.5.3 उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA)

जनवरी 1994 में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको ने उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) किया और वहाँ विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बना दिया। माना जाता है कि नाफ्टा (NAFTA) ने वर्ष 1994 से सभी तीन सदस्य देशों के लोगों के लिए आर्थिक विकास और जीवन स्तर में वृद्धि की है। यह पूरे महाद्वीप में व्यापार और निवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं को मजबूत करके हासिल किया गया है। इसके लिए मुक्त व्यापार समझौता (FTA) तैयार करके अमल में लाया गया।

इस समझौते में अनेक आयाम शामिल हैं, यथा माल का व्यापार (Trade in Goods), स्रोत संबंधी नियम, व्यापार में तकनीकी बाधाएँ (TBT), सरकारी खरीद, निवेश, सेवाएँ और संबंधित मामले, बौद्धिक संपदा तथा प्रशासनिक और संस्थागत प्रावधान। नाफ्टा ने कनाडा और मैक्सिको दोनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना निर्यात बढ़ाने में सक्षम बनाया है। अब तीनों देशों के विनिर्माता एक बड़ी, अधिक एकीकृत और कुशल उत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काम करके अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हैं।

नाफ्टा के तहत उक्त देश समानांतर पर्यावरण और श्रम सहयोग समझौतों के अत्यधिक सफल उपागम को प्रस्तुत करने में भी सक्षम हैं। नाफ्टा द्वारा प्रचारित आर्थिक एकीकरण ने पूरे क्षेत्र में बेहतर पर्यावरण प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है।

पर्यावरण सहयोग पर उत्तरी अमेरिकी समझौते (NAAEC) के माध्यम से तीनों भागीदार देश पर्यावरण कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। श्रम सहयोग पर उत्तरी अमेरिकी समझौते (NAALC) के माध्यम से मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका श्रमिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नाफ्टा को प्रायः एक क्षेत्रीय व्यापारिक गुट के एक सफल उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिसने व्यापार सृजन के प्रभावों के माध्यम से सहभागी देशों के लिए कल्याणकारी लाभ दर्शाए है।.

14.5.4 आसियान (ASEAN)

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) की स्थापना 1967 में पाँच मूल सदस्य देशों – इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी। इसमें ब्रुनेई दारुस्सलाम वर्ष 1984 में, वियतनाम वर्ष 1995 में, लाओस और म्यांमार वर्ष 1997 में और कंबोडिया वर्ष 1999 में शामिल हुए, जिससे यह आसियान–10 (ASEAN-10) बन गया।

दक्षेस या आसियान की शुरुआत राजनीतिक मुद्दों पर जोर देने के साथ हुई थी, परंतु हाल के दिनों में, विशेषकर वर्ष 1997 के एशियाई संकट के बाद से, आर्थिक एकीकरण प्राथमिकता बन गया है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर प्राधारिक समझौता (Framework Agreement) वर्ष 1992 में चौथे आसियान शिखर सम्मेलन, सिंगापुर में अपनाया गया था। इसमें आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFTA) की दिशा में एक योजना की शुरुआत शामिल थी।

इस योजना (AFTA) का रणनीतिक उद्देश्य एकल उत्पादन इकाई के रूप में आसियान क्षेत्र के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना है। सदस्य देशों के बीच टैरिफ और गैर–टैरिफ

बाधाओं को समाप्त करने से वृहत्तर आर्थिक दक्षता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की आशा है।

वर्ष 1995 में बैंकॉक में आयोजित पाँचवें आसियान शिखर सम्मेलन ने वृहत्तर आर्थिक एकीकरण हेतु एजेंडा अपनाया। तदंतर वर्ष 1997 में आसियान नेताओं ने आसियान विजन 2020 अपनाया, जिसने इस क्षेत्र के भीतर घनिष्ठतर आर्थिक एकीकरण लाने के उद्देश्य से गतिशील विकास में आसियान भागीदारी का आह्वान किया।

उक्त दृष्टिकोण के प्रकथन में एक ऐसा स्थिर, समृद्ध और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी आसियान आर्थिक क्षेत्र बनाने का भी संकल्प लिया गया जिसमें माल, सेवाओं, निवेश, पूँजी और समान आर्थिक विकास का मुक्त प्रवाह हो तथा गरीबी और सामाजिक–आर्थिक विषमताएँ कम हों। आसियान सहयोग के परिणामस्वरूप अधिक क्षेत्रीय एकीकरण हुआ है। आसियान देशों के पर्यटक स्वयं इस क्षेत्र में पर्यटन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आसियान आर्थिक सहयोग व्यापक है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं – व्यापार, निवेश, उद्योग, सेवाएँ, वित्त, कृषि, वानिकी, ऊर्जा, परिवहन और संचार, बौद्धिक संपदा, लघु एवं मध्यम उद्यम और पर्यटन।

14.5.5 सार्क (SAARC)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) की स्थापना तब हुई जब इसके चार्टर को औपचारिक रूप से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों द्वारा अपना लिया गया। सार्क (SAARC) नामक यह संघ दक्षिण एशिया के लोगों को परस्पर मैत्री, विश्वास और समझ की भावना से मिलकर काम करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा क्षेत्र में त्वरित आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

अब तकनीकी समितियों के माध्यम से अपनाए जाने वाले पुनर्गठित क्षेत्रीय एकीकृत कार्यक्रम के तहत सहयोग के इन क्षेत्रों को शामिल करके चला जाता है – कृषि और ग्रामीण विकास; स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिविधियाँ; महिलाएँ, युवा और बच्चे; पर्यावरण और वानिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मौसम विज्ञान; परिवहन; तथा मानव संसाधन विकास। साथ ही, इन क्षेत्रों में कुछ कार्य समूह भी स्थापित किए गए हैं – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT); जैव प्रौद्योगिकीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR); पर्यटन; और ऊर्जा।

सार्क में शिखर सम्मेलन ही सर्वोच्च प्राधिकरण होते हैं और इन्हें वार्षिक रूप से आयोजित किया जाना आवश्यक होता है। वर्ष 1993 में दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौते (SAPTA) पर हस्ताक्षर किए गए और व्यापार वार्ता के चार दौर संपन्न हो गए।

तदंतर जनवरी 2004 में दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ (SAEU) की ओर बढ़ने के उद्देश्य से इस्लामाबाद में बारहवें शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते (SAFTA) पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि जुलाई 2006 से लागू हुआ। इसी शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क सामाजिक चार्टर पर भी हस्ताक्षर किए गए ताकि विभिन्न

सामाजिक मुद्दों का समाधान किया जा सके, जैसे जनसंख्या स्थिरीकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवा लामबंदी, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा देना, तथा बच्चों की सुरक्षा, जो कि सभी दक्षिण एशियाई लोगों के कल्याण और कुशलक्षेम की कुंजी हैं।

14.6 अंतर्राष्ट्रीय वित्त

अंतर्राष्ट्रीय वित्त के अंतर्गत मौद्रिक अंतर्क्रियाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये मुद्दे कम से कम दो या दो से अधिक देशों के बीच होते हैं। मुद्राओं की विनिमय दरें, विश्व की मौद्रिक प्रणाली, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय वित्त के कार्यक्षेत्र में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त का अस्तित्व इस तथ्य में निहित है कि व्यवसायों, सरकारों और संगठनों की आर्थिक गतिविधियाँ विभिन्न राष्ट्रों के अस्तित्व से प्रभावित होती हैं। देश प्रायः परस्पर उधार लेते हैं और उधार देते हैं। ऐसा करने में कई देश अपनी मुद्राओं का उपयोग करते हैं। एक मुद्रा दूसरी मुद्रा की तुलना में अपने मूल्य के मामले में भिन्न होती है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभिन्न मुद्राओं की तुलना करने और यह समझने का एक तरीका प्रदान करता है कि आयात का भुगतान कैसे किया जाए और उन कीमतों का निर्धारक कारक क्या है जिन पर मुद्राओं का लेन–देन किया जा रहा है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) कुछ उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन हैं।

जैसा कि हमने पिछले पाठांशों में चर्चा की थी कि व्यापार किसी देश के लिए विकास का इंजन होता है और वैश्वीकरण के कारण व्यापार का महत्व कई गुना बढ़ चुका है। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता बनने के बाद अमेरिका का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय देनदार के रूप में उभरना एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है। इसका अंतर्राष्ट्रीय वित्त और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के काम करने के ढंग पर प्रभाव पड़ता है।

14.6.1 अंतर्राष्ट्रीय वित्त का महत्व

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय वित्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके महत्व में निहित कारण निम्नलिखित हैं –

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त विनिमय दरों का पता लगाने, मुद्रास्फीति दरों की तुलना करने, अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने, अन्य देशों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने और विदेशी बाजारों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे हमें मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों को निर्धारित करने में सक्षम बनाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त इन दरों के परिकलन में मदद करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय निवेश निर्णय अनेक आर्थिक कारकों पर आधारित होते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक कारक यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि विदेशी ऋण प्रतिभूतियों के साथ निवेशकों का पैसा सुरक्षित है अथवा नहीं।

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) का प्रयोग करना अंतर्राष्ट्रीय वित्त के कई चरणों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इन मानकों को अपनाने वाले देशों द्वारा दिए गए वित्तीय विवरण एक समान होते हैं और व्यवस्था को एकरूपता प्रदान करते हैं। यह कई देशों को एक समान सूचना प्रणाली अपनाने करने में मदद करता है।
- उक्त मानक (IFRS) जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त का एक हिस्सा है, एकल लेखा मानक पर रिपोर्टिंग के नियमों का पालन करके पैसे बचाने में भी मदद करती है।
- वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय वित्त की महत्ता बढ़ी है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मूल बातें समझने में मदद करता है और उनके बीच संतुलन बनाए रखता है।
- कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखती है। किसी ठोस और सुदृढ़ वित्त मापदंड के बिना सभी राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, जिससे कई समस्याएँ पैदा होंगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त उस मुद्दे को दूर रखने में मदद करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन अंतर्राष्ट्रीय वित्त विवादों के प्रबंधन में मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं।

किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के अस्तित्व मात्र का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट की संभावनाएँ होती हैं। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के बिना विवादों की संभावना और तदनुसार किसी परिणामी गड़बड़ी स्पष्ट होती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को अनुशासित स्थिति में रखने में मदद करता है।

हाल के दशकों में वित्तीय अर्थव्यवस्थाएँ विश्व भर में तेजी से आपस में जुड़ी हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर महसूस किया गया है। वित्तीय वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ–साथ निवेशकों एवं धन सृजनकर्ताओं दोनों को पर्याप्त लाभ प्रदान किया है। तथापि, इसका वित्तीय बाजारों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है।

14.6.2 वित्तीय वैश्वीकरण

जब हम वित्तीय वैश्वीकरण के विषय में बात करते हैं तो चार ऐसे प्रमुख कारक होते हैं जो इसकी प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। ये कारक निम्नवत् हैं –

- *सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में प्रगति* – तकनीकी प्रगति ने बाजार प्रतिभागियों और सरकारों को वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन हेतु आवश्यक जानकारी एकत्र करने में कहीं अधिक कुशल बना दिया है।
- *राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का वैश्वीकरण* – आर्थिक वैश्वीकरण ने विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर उत्पादन, उपभोग और निवेश का विस्तार कर दिया है। चूँकि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम कर दिया गया है, वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- *राष्ट्रीय वित्तीय और पूँजी बाजारों का उदारीकरण* – उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से सुधार और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप

अत्यधिक वित्तीय नवाचारों का प्रसार हुआ है। इसने अंतर्राष्ट्रीय पूँजी संचलन के विकास में वृद्धि की है।

- *मध्यस्थ सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा* – तकनीकी प्रगति और वित्तीय उदारीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा कई गुना बढ़ गई है। संस्थागत निवेशकों सहित गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का एक नया वर्ग भी उभरा है।

वित्तीय वैश्वीकरण के अनेक लाभ हैं तो इसके कुछ जोखिम भी हैं। आइए, इन पर चर्चा करें –:

- वित्तीय वैश्वीकरण के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि ''ऋण संकट'' का जोखिम बेहद निम्न स्तर तक कम हो गया है। जब बैंक दबाव में होते हैं तो वे अब अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार से धन जुटा सकते हैं।
- अधिक विकल्पों के साथ ऋणग्राही और निवेशक अपने वित्तपोषण पर बेहतर मूल्य निर्धारण का लाभ उठाते है। निगम निवेश का अधिक सस्ते में वित्तपोषण करने में सक्षम होते हैं।
- वित्तीय वैश्वीकरण का एक दोष यह है कि बाजार अब बेहद अस्थिर हैं और यह वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हो सकता है। वित्तीय वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों में जोखिम संतुलन में बदलाव ला दिया है।
- वित्तीय वैश्वीकरण के साथ उभरते बाजारों में ऋण–पात्र बैंक और व्यवसाय अब अपनी उधारी लागत को कम कर सकते हैं। बहरहाल, कमजोर या खराब प्रबंधन वाले बैंकों के साथ उभरते बाजार जोखिम में हैं।

सन 1990 के दशक के संकटों ने एक विवेकपूर्ण संप्रभु ऋण प्रबंधन, प्रभावी पूँजी खाता उदारीकरण और घरेलू वित्तीय प्रणालियों के प्रबंधन के महत्व को दर्शाया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली निम्नलिखित तरीकों से एक रक्षोपाय के रूप में कार्य करती है –

- निजी वित्तीय संस्थान और बाजार के प्रतिभागी अब अपने व्यवसायों को अच्छी तरह से नियंत्रित करके और अनावश्यक जोखिम लेने से बचकर वित्तीय स्थिरता में योगदान कर सकते हैं।
- वित्तीय स्थिरता एक वैश्विक लोकहित है, इसलिए सरकारें और नियामक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका का दायरा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय रूप लेता जा रहा है।.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक प्रमुख भूमिका–निर्वाहक भी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसकी वैश्विक निगरानी पहल भी एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 2

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।
ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपनी प्रगति की जाँच करें।

1) गैट क्या है और लाभकारी व्यापार के संबंध में यह कैसे काम करता है?

.....

.....

.....

2) कुछ व्यापारिक गुटों के नाम बताइए। उनमें से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

3) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता क्यों है? स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

4) वित्तीय वैश्वीकरण के लाभ और जोखिमों की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

14.7 सारांश

इस इकाई की शुरुआत हमने विभिन्न व्यापार सिद्धांतों को समझते हुए की, जिन्होंने ऐसे विभिन्न आधारों के अस्तित्व का संकेत दिया जिन पर कोई दो देश लाभकारी व्यापार में संलग्न हो सकते हैं। पूर्ण लाभ के आधार ने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में हेक्शेर–ओहलिन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसने किसी देश के बंदोबस्ती कारकों और तीव्रता गुणांक तथा उसकी उत्पादन प्रक्रियाओं पर जोर दिया।

देश आमतौर पर व्यापार सुरक्षा के लिए कुछ व्यापार बाधाओं का पालन करते हैं। ये बाधाएँ टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाओं की श्रेणी में आती हैं। उक्त व्यापार सिद्धांत भी देशों को व्यापार समझौतों के मार्ग पर ले जाते हैं। इस तरह के समझौते किसी देश की व्यापार नीति के मापदंडों का हिस्सा होते हैं। ये समझौते व्यापार से लाभ उठाने के लिए विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं।

इस तरह के समझौतों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने के लिए यूरोपीय संघ, एपेक और नाफ्टा जैसे विभिन्न व्यापारिक समझौतों पर चर्चा की गई।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं के कम होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों का महत्व भी बढ़ गया है। इकाई में वित्तीय वैश्वीकरण की प्रेरक शक्तियों तथा वित्तीय वैश्वीकरण के जोखिमों और लाभों पर चर्चा की गई है। इस प्रकार की वित्तीय प्रणालियाँ विभिन्न राष्ट्रों की सुरक्षा करती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

14.8 शब्दावली

तुलनात्मक लाभ — यदि दूसरे देश की तुलना में अपने ही देश में किसी वस्तु 'A' के उत्पादन की अवसर लागत कम हो तो उस देश को उस वस्तु का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ होता है।

व्यापार सृजन — वाइनर ने वर्ष 1950 में व्यापार सृजन की अवधारणा प्रस्तुत की। यह ऐसा व्यापार है जो एक अधिमान्य व्यापार व्यवस्था के सदस्यों के बीच होता है और जो अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (PTA) के अभाव में आयात करने वाले देश में उत्पादित होने वाले उत्पादों की जगह ले लेता है। व्यापार सृजन आयातक देश के लिए कल्याणकारी सुधार से जुड़ा है क्योंकि यह आयातित वस्तु की लागत को कम कर देता है।

व्यापार पथांतरण — वाइनर ने वर्ष 1950 में व्यापार पथांतरण की अवधारणा प्रस्तुत की। यह ऐसा व्यापार है जो एक अधिमान्य व्यापार व्यवस्था के सदस्यों के बीच होता है और जो अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (PTA) से बाहर के देश से आयात किए जाने वाले माल का स्थान ले लेता है। यह आयात करने वाले देश के कल्याण में कमी कर देने से जुड़ा है क्योंकि इससे आयातित माल की लागत बढ़ जाती है।

बंदोबस्ती कारक — भूमि, श्रम और पूँजी जैसे संसाधनों के साथ किसी देश की अक्षयनिधि।

तीव्रता गुणांक — तीव्रता गुणांक किसी दिए गए उद्योग के लिए अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में किसी एक कारक (यथा भूमि या श्रम या पूँजी) बनाम अन्य कारकों का सापेक्ष महत्व होता है, जो कि आमतौर पर अन्य उद्योगों की तुलना में होता है। तीव्रता गुणांकों को अधिकतर सामान्य कारक कीमतों पर नियोजित कारक मात्राओं के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इन्हें कभी–कभी कारक शेयरों से अथवा

कारकों के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दरों से भी परिभाषित किया जाता है।

टैरिफ जब किसी वस्तु का आयात किया जाता है तो टैरिफ एक प्रकार का कर होता है।

क्षेत्रीय व्यापारिक गुट ऐसे देशों का समूह जो भौगोलिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आमतौर पर किसी प्रकार की अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (PTA) में निकटता से जुड़े होते हैं।

14.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

सल्वाटोर, डोमिनिक, *इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स*, ग्यारहवाँ संस्करण विले, संयुक्त राज्य अमेरिका।

क्रुगमैन, पॉल आर., मौरिस ओब्स्टफेल्ड, मार्क. जे. मेलिट्ज, *इंटरनेशनल ट्रेड : थ्योरी एंड पॉलिसी*, ग्यारहवाँ संस्करण, पियर्सन।

क्रुगमैन, पॉल आर., मौरिस ओब्स्टफेल्ड, मार्क. जे. मेलिट्ज, *इंटरनेशनल फाइनैंस : थ्योरी एंड पॉलिसी*, दसवाँ संस्करण, पियर्सन।

14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) (पाठांश 14.2.1 देखें) राष्ट्र X में वस्तु A की एक इकाई के निर्माण के लिए 10 इकाई श्रम लगता है, परंतु राष्ट्र Y के मामले में 20 श्रम इकाइयाँ हैं। तब राष्ट्र X को वस्तु A के उत्पादन में पूर्ण लाभ होता है।

2) (पाठांश 14.2.2 देखें) यदि किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत दूसरे देश की तुलना में अपने देश में कम हो तो उस देश को उक्त वस्तु का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ होगा ।

3) (पाठांश 14.2.3 देखें) हेक्शर–ओहलिन (H-O) प्रमेय से ज्ञात होता है कि तुलनात्मक लाभ राष्ट्रों के संसाधनों और उत्पादन की तकनीक के बीच बातचीत से प्रभावित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, व्यापार के निर्धारक तत्व देशों के बंदोबस्ती कारक और माल का तीव्रता गुणांक होते हैं। कोई देश उस वस्तु में विशेषज्ञता प्राप्त करता है और उसका निर्यात करता है जो अपने सर्वाधिक प्रचुर कारक होने का लाभ दर्शाती है।

4) (पाठांश 14.3.1 देखें) टैरिफ एक कर होता है, जो कि किसी वस्तु के आयात पर लगाया जाता है। तैयार और मध्यवर्ती दोनों प्रकार के माल के आयात पर टैरिफ लागू किया जा सकता है। टैरिफ विशिष्ट या यथामूल्य हो सकते हैं। किसी आयातित वस्तु पर टैरिफ उस वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्राप्त मूल्य को बढ़ा देता है। यही प्रभाव प्रायः टैरिफ का मुख्य उद्देश्य होता है – घरेलू उत्पादकों को उन कम कीमतों से बचाने के लिए जो आयात प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होंगी। इन मूल्य परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को आयात करने वाले देश में हानि होती है और निर्यातक

देश में लाभ प्राप्त होता है। उत्पादकों को आयात करने वाले देश में लाभ होता है और निर्यातक देश में हानि होती है।

बोध प्रश्न 2

1) (संदर्भ पाठांश 14.4) कुल 23 देशों के एक समूह ने एक अनंतिम नियमावली के तहत व्यापार वार्ता शुरू की, जिसे प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता या गैट (GATT) कहा जाने लगा। संगठन का पुनः पतन रोकने के लिए अनुबंधन की प्रक्रिया अस्तित्व में है। इसमें बाउंड टैरिफ दर का अर्थ है कि टैरिफ लगाने वाला देश भविष्य में दर न बढ़ाने के लिए सहमत है। यहाँ बाउंड टैरिफ के अलावा गैट–विश्व व्यापार संगठन (GATT-WTO) प्रणाली भी आमतौर पर व्यापार में गैर–टैरिफ हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास करती है।

2) (पाठांश 14.5 देखें) एपेक, असियान, नाफ्टा, यूरोपीय संघ आदि।

3) (पाठांश 14.6.1 देखें) अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभिन्न मुद्राओं की तुलना करने और यह समझने का वह ढंग बताता है जिससे आयात का भुगतान किया जाता है और कीमतों का वह निर्धारक कारक ज्ञात किया जाता है जिस पर मुद्राएँ व्यापार करती हैं।

4) (पाठांश 14.6.2 देखें) ऋण संकट, कमजोर या खराब प्रबंधन वाले बैंकों के साथ उभरते बाजार जोखिम में हैं तथा ऋणग्राहियों और निवेशकों के लिए अब पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं।

शब्दावली

अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीयवादियों का मानना है कि अधिकांश आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ वैश्विक स्तर पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय रूप से की जाती हैं।

अधिशेष श्रम वे श्रमिक जिन्हें कम या बिना किसी संभावित लागत पर हटाया जा सकता है। यह श्रमबल का भौतिक सीमांत उत्पाद शून्य के बराबर होने की स्थिति होती है।

अनुक्रमिक चुकौती यह पदबंध उस विशेषता को इंगित करता है कि जब चुकौती लगभग एक माह के भीतर शुरू हो जाती है तो चुकौती छोटी और नियमित किश्तों में की जाती है।

अनैच्छिक बेरोजगारी यह तब व्याप्त होती है जब कोई व्यक्ति अभिभावी वेतन दर पर काम करने के लिए इच्छुक और सक्षम होता है परंतु उसे नौकरी नहीं मिल रही होती है।

अर्थशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य अर्थशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की बढ़ती प्रायिकता, विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक परस्पर निर्भरता और उनके एकीकरण की सुविधा में वृद्धि पर बल देता है।

आकस्मिक नवीनीकरण संयुक्त देयता ऋणों के संदर्भ में आकस्मिक नवीनीकरण का अर्थ है कि यदि समूह का कोई सदस्य बाकीदारी करता है तो समूह के किसी भी सदस्य को और ऋण प्राप्त नहीं होता है। यदि समूह चुकौती कर देता है तो भविष्य के ऋण सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

आचारिक संकट समस्या यह छिपी हुई कार्रवाई की समस्या को संदर्भित करता है (जैसे इस विषय में जानकारी का अभाव कि ऋण का उपयोग कैसे किया जाएगा अथवा ऋण चुकौती निर्णय के विषय में जानकारी का अभाव)।

आबंधक सामाजिक पूँजी वह पूँजी जो उन व्यक्ति–समूहों के बीच दृढ़ एवं घनिष्ठ संबंधों को इंगित करती है जो सबसे अधिक सजातीय होते हैं।

आयात–निर्यात स्थिति यह व्यापार स्थिति किसी देश के आयात की कीमतों और निर्यात की कीमतों के अनुपात को इंगित करती है।

आयु–विशिष्ट प्रजनन दर यह प्रति वर्ष एक विशेष आयु वर्ग में महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है।

आरक्षण वेतन वह न्यूनतम मजदूरी जिस पर कोई व्यक्ति काम करने या नौकरी स्वीकार करने को तैयार हो।

उत्सर्जन कर

उत्सर्जन कर एक ऐसा कर अथवा आर्थिक दंड है जो सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदूषणकर्ताओं पर लगाया जाता है। यह शुल्क परिवेशी पर्यावरण में उत्सर्जन की प्रति इकाई रुपयों के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है।

ऋण नियंत्रण

ऋण नियंत्रण एक ऐसी स्थिति को इंगित करता है जिसमें चालू ब्याज दर पर ऋणदाता अधिक ऋण प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होता है, भले ही ऋणग्राही अधिक धन उधार लेना चाहता हो।

औसत मृत्यु दर

यह किसी देश विशेष में आयु–विशिष्ट मृत्यु दरों के साथ–साथ उस देश में समग्र आयु वितरण से ज्ञात संयोजन होता है।

काश्तकारी

यह किसी काश्तकार द्वारा किसी अन्य की भूमि या संपत्ति पर अस्थायी स्वामित्व है।

कॉमन–पूल संसाधन

कॉमन–पूल संसाधन आमतौर पर निर्बाध–प्रवेश संसाधन होते हैं और अनेक लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

कॉमन्स की त्रासदी

यदि लोग स्वतंत्र रूप से, युक्तिपूर्वक और अपने वैयक्तिक हितों के अनुपालन को ही ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो वे अपने समुदायों के सार्वजनिक हितों के विरुद्ध ही जाएँगे और धरती के प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर बैठेंगे। सार्वजनिक संसाधनों का यह अत्यधिक प्रयोग ही 'कॉमन्स की त्रासदी' कहलाता है।

कुल प्रजनन दर

उस महिला को पैदा होने वाले बच्चों की संख्या जो अपने बच्चे के जन्म के वर्षों के अंत तक जीवित रहती है और प्रचलित आयु–विशिष्ट प्रजनन दर के अनुसार बच्चे पैदा करती है। इसकी गणना विभिन्न आयु वर्गों में सभी आयु–विशिष्ट प्रजनन दरों को जोड़कर की जाती है।

केंद्र

यह उन्नत देशों के समूह को इंगित करता है। आश्रयता सिद्धांत के प्राधार में इन देशों को 'प्रमुख' भी कहा जाता है।

कोस प्रमेय

कोस प्रमेय अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोस द्वारा विकसित एक विधिसम्मत एवं आर्थिक सिद्धांत है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि जहाँ बिना किसी लेन–देन लागत के साथ पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार विद्यमान होते हैं, इस बात पर ध्यान दिए बिना ही उत्पादन–इष्टतम आवंटन में और उससे आदानों और प्रदाओं का एक दक्ष सेट चुन लिया जाता है कि स्वामित्व अधिकार किस प्रकार वितरित किए गए।

गैर–सरकारी संगठन (NGOs) वे संगठन जो सरकारी प्रभाव से परे होते हैं और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं।

छूट दर वर्तमान मूल्य गणना में वह वार्षिक दर जिस पर भावी मूल्यों को वर्तमान मूल्यों के साथ तुलनीय बनाने के लिए घटाया जाता है।

जनसंख्या–गरीबी चक्र सिद्धांत यह सिद्धांत बताता है कि कैसे गरीबी और उच्च जनसंख्या वृद्धि विकट रूप ले लेती हैं और अल्पविकास की स्थिति से जुड़ी आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को और अधिक गंभीर बना देती हैं।

जनसंख्या वृद्धि दर इसकी गणना जन्म दर घटा मृत्यु दर के रूप में की जाती है और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि मृत्यु से अधिक जन्म या तकनीकी शब्दों में, प्रजनन दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को मापती है। जनसंख्या वृद्धि की दर जनसंख्या की वृद्धि दर होती है, जिसकी गणना आप्रवास और उत्प्रवास के समायोजन के बाद वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है।

जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत उच्च जन्म दर और मृत्यु दर की विशेषता वाली आभासी स्थिर विकास अवस्था (चरण 1) से जनसंख्या वृद्धि दरों की चरणबद्ध प्रक्रिया उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के साथ एक स्थिर, निम्न विकास अवस्था (चरण 3) में तेजी से उस विकास अवस्था के माध्यम से होती है जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों दरें कम (चरण 2) होती हैं।

टैरिफ जब किसी वस्तु का आयात किया जाता है तो टैरिफ एक प्रकार का कर होता है।

तीव्रता गुणांक तीव्रता गुणांक किसी दिए गए उद्योग के लिए अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में किसी एक कारक (यथा भूमि या श्रम या पूँजी) बनाम अन्य कारकों का सापेक्ष महत्व होता है, जो कि आमतौर पर अन्य उद्योगों की तुलना में होता है। तीव्रता गुणांकों को अधिकतर सामान्य कारक कीमतों पर नियोजित कारक मात्राओं के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इन्हें कभी–कभी कारक शेयरों से अथवा कारकों के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दरों से भी परिभाषित किया जाता है।

तुलनात्मक लाभ यदि दूसरे देश की तुलना में अपने ही देश में किसी वस्तु 'A' के उत्पादन की अवसर लागत कम हो तो उस देश को उस वस्तु का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ होता है।

द्विविधता यह दो भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के अस्तित्व को इंगित करती है, जहाँ प्रत्येक के पास अपनी भिन्न प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रक्रिया

और आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि में देश के कुछ भागों में यंत्रीकृत कृषि होती है जबकि शेष भागों में परंपरागत कृषि होती है।

नकारात्मक बाह्यता यदि किसी एक व्यक्ति के कार्यों का किसी दूसरे व्यक्ति पर अनुपयोगी अथवा हानिकारक प्रभाव पड़ता हो तो इसे नकारात्मक बाह्यता कहा जाएगा।

नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय संसाधनों को नाना रूपों के बीच असीम और प्रतिस्थापन योग्य माना जाता है।

निर्यात–उन्मुखीकरण यह निर्यात–आधारित विकास की रणनीति को इंगित करता है। ऐसी रणनीति का विलोम आयात–प्रतिस्थापन हो सकता है।

निष्कासन यह तब होता है जब किराए का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है अथवा आवश्यक उद्यम का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है और इस कारण भूमि के काश्तकार को स्वामी की संपत्ति छोड़ देने के लिए कह दिया जाता है। काश्तकार को अभिप्रेरित बनाए रखने के लिए भूस्वामी प्रायः इसे धमकी के रूप में प्रयोग करता है।

पंचायती राज संस्थाएँ जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से युक्त ग्रामीण स्थानीय शासन की तीन–स्तरीय संस्थाएँ।

परिधि यह अल्पविकसित देशों के समूह को इंगित करती है। आश्रयता सिद्धांत के प्राधार में केंद्र और परिधि के बीच एक असमान आदान–प्रदान होता है, जिससे परिधि अल्पविकसित ही बनी रहती है।

परिवर्तनवादी दृष्टिकोण राष्ट्र राज्य शक्तिशाली बना रहता है और जो भी चुनौतियाँ होती हैं उनका पुनर्गठन, सुधार और वैश्विक शासन के नए रूपों को समायोजित करके सामना किया जा सकता है।

पिगोवियनकर एक प्रदूषण कर जो किसी प्रदूषणकारी फर्म द्वारा समाज को प्रदूषित कर उसे सामाजिक क्षति पहुँचाए जाने अथवा उस पर सामाजिक लागत थोपे जाने को बेअसर करता है।

पुनर्वास यह उन लोगों को फिर से बसाने की प्रक्रिया है जिनकी भूमि किसी नए क्षेत्र में अधिग्रहित की गई हो।

पुनर्स्थापन यह भूमि को उसकी पूर्व या मूल स्थिति में बहाल करने की प्रक्रिया को इंगित करता है।

प्रतिकूल चयन यह एक ऐसी समस्या को इंगित करता है जिसमें ऋणग्राही के अभिलक्षण ज्ञात नहीं होते हैं। औपचारिक संस्थागत ऋणदाता के पास 'ऋणग्राहियों की गुणवत्ता' और उनके जोखिम लेने

वाले व्यवहार (यथा, ऋण लेने वाला अच्छा या सुरक्षित ऋणग्राही हो अथवा बुरा या जोखिमपूर्ण ऋणग्राही हो) के विषय में विश्वसनीय जानकारी नहीं हो सकती है।

प्रख्यात डोमेन का सिद्धांत

इसका सामान्य अर्थ है कि सत्तारूढ़ सरकार को आम जनता के हित में किसी भी संपत्ति को ले लेने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने को तैयार न हो तो यह सिद्धांत सरकार को उस भूमि का बलपूर्वक अधिग्रहण कर लेने की अनुमति देता है।

प्रतिरोधसमस्या

यह एकाधिकार शक्ति का एक रूप है जो संभावित रूप से भूमि अधिग्रहण के दौरान वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ किसी परियोजना के लिए भूमि का एक बड़ा हिस्सा आवश्यक होता है (जैसे अवसंरचना, उद्योग, खनन, शहरी आवास आदि)। एक बार अधिग्रहण शुरू होने के बाद कुछ भूस्वामी यह जानकारी मिलने पर कि चालू परियोजना के पूरा होने के लिए उनकी भूमि आवश्यक है, अपनी अवसर लागत से अधिक कीमत पाने के लिए प्रतिरोध (holdout) कर सकते हैं।

प्रच्छन्न बेरोजगारी

यदि हम मान लें कि कहीं पर एक ऐसा पूँजीवादी क्षेत्र भी है जो सीमांत उत्पाद के अनुसार ही भुगतान करता है, तब अर्थव्यवस्था एक ऐसी वेतन दर (अकुशल श्रमिक के लिए) दर्शाएगी जो कहीं और सीमांत उत्पाद का सही मापदंड होगी, तथा यहाँ दक्षता लाभ तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक पारंपरिक गतिविधि पर सीमांत उत्पाद वेतन से कम रहेगा, चाहे वह शून्य हो या न हो। इस विस्तारित अवधारणा को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी (disguised unemployment)के रूप में जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की मात्रा को मोटे तौर पर पारंपरिक गतिविधि में विद्यमान श्रम निवेश और उस श्रम निवेश के बीच अंतर से मापा जा सकता है जो सीमांत उत्पाद को वेतन के बराबर तय करता हो।

बंदोबस्ती कारक

भूमि, श्रम और पूँजी जैसे संसाधनों के साथ किसी देश की अक्षयनिधि।

बटाईदारी

यह एक प्रकार का काश्तकारी अनुबंध है, जिसमें काश्तकार को किराए के रूप में उत्पादित फसल के हिस्से के बदले भूमि पर खेती करने की अनुमति दे दी जाती है।

बाजार की विफलता

यह पदबंध मुक्त बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं (इस मामले में ऋण) के अकुशल वितरण को इंगित करता है। यह तब होता है जब वस्तुओं या सेवाओं की माँग वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बराबर नहीं होती है। इस इकाई में दो मुख्य प्रकार

की बाजार विफलता – विषम सूचना और संकेंद्रित बाजार शक्ति – पर चर्चा की गई।

भागीदारी निबाध

आरक्षण वेतन को परिभाषित करने के लिए भागीदारी निबाध का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार, यदि फर्म आरक्षण वेतन से कम वेतन की पेशकश करती है तो कर्मचारी नौकरी स्वीकार नहीं करेगा।

भूमि अधिग्रहण

इसका अर्थ पहले से ही विभिन्न प्रयोगों के तहत भूमि के किसी बड़े हिस्से को अर्जित करना होता है। यह आमतौर पर भूमि के उस बड़े खंड को प्राप्त करके किया जाता है जो पहले से ही विभिन्न भूमि प्रयोगों के तहत हो है और विभिन्न हितधारकों के साथ निहित हो।

भूमि सुधार

ये सुधार भूस्वामित्व को धनी जमींदारों (अधिक शक्तिशाली लोगों) से गरीब या अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली लोगों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को इंगित करते हैं। ये आमतौर पर भूस्वामित्व को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों को बदलकर किया जाता है।

मानव पूँजी

इसको उस श्रमबल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कुशल है, परिष्कृत मशीनरी को संभाल सकता है और मशीनों का उपयोग करने में नवप्रवर्तनशील है। कौशल, क्षमताओं, आदर्शों, स्वास्थ्य और अवस्थानों सहित मानव मात्र में निहित लाभकारी निवेश प्रायः शिक्षा, ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण कार्यक्रमों और चिकित्सा देखभाल पर व्यय के परिणामस्वरूप होता है।

माल्थुसियन जनसंख्या जाल

अठारहवीं शताब्दी में थॉमस माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। माल्थस ने किसी देश की जनसंख्या के लिए इस सार्वभौमिक प्रवृत्ति को तब तक स्वयं सिद्ध माना जब तक कि उसे घटती खाद्य आपूर्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता कि वह हर 30 से 40 वर्षों में गुणोत्तर आरोहण कर दोगुनी हो जाती है। साथ ही, स्थिर कारक भूमि पर घटते प्रतिफल के कारण खाद्य आपूर्ति मोटे तौर पर अंकगणितीय दर से ही विस्तारित हो सकती है। चूँकि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के पास काम करने के लिए कम भूमि होगी, खाद्य उत्पादन में उसका मामूली योगदान वास्तव में घटने लगेगा। अब चूँकि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि बढ़ती जनसंख्या के साथ तालमेल नहीं रख सकती, प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन) में इतने नीचे तक गिरावट आने की प्रवृत्ति होगी कि स्थिर जनसंख्या नाममात्र को निर्वाह स्तर पर या फिर उससे किंचित्

ऊपर दिखाई दे।

मात्रानुपाती दर — मात्रानुपाती या उजरती दर का अर्थ होता है कि किसी कर्मचारी को दिया गया पारिश्रमिक उसके द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों पर आधारित है।

युवा निर्भरता अनुपात — यह किसी देश में 15 वर्ष से कम आयु के युवाओं और 15–59 आयु वर्ग के कार्यशील व्यक्तियों की जनसंख्या में का अनुपात होता है।

योजक सामाजिक पूँजी — वह पूँजी जो व्यक्तियों के विषम समूहों के बीच अदृढ़ संबंधों को इंगित करती है और इन समूहों के बीच मतभेदों को पाटती है।

विश्व–नागरिक परिप्रेक्ष्य — विश्वव्यापी दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर बल देता है कि सभी मनुष्य एक वैश्विक समुदाय के सदस्य हैं।

वैश्वीकरण — वे सभी प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा विश्व भर के लोग एक एकल विश्व समाज में समाविष्ट हैं।

व्यापार पथांतरण — वाइनर ने वर्ष 1950 में व्यापार पथांतरण की अवधारणा प्रस्तुत की। यह ऐसा व्यापार है जो एक अधिमान्य व्यापार व्यवस्था के सदस्यों के बीच होता है और जो अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (PTA) से बाहर के देश से आयात किए जाने वाले माल का स्थान ले लेता है। यह आयात करने वाले देश के कल्याण में कमी कर देने से जुड़ा है क्योंकि इससे आयातित माल की लागत बढ़ जाती है।

व्यापार संरचना — व्यापार की संरचना निर्यात और आयात में माल की संरचना को इंगित करती है। यह संरचना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण होती है कि अल्पविकसित देशों के निर्यात में प्राथमिक वस्तुओं का वर्चस्व होता है जबकि उनके आयात में मुख्य रूप से निर्मित उत्पाद शामिल होते हैं।

व्यापार सृजन — वाइनर ने वर्ष 1950 में व्यापार सृजन की अवधारणा प्रस्तुत की। यह ऐसा व्यापार है जो एक अधिमान्य व्यापार व्यवस्था के सदस्यों के बीच होता है और जो अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (PTA) के अभाव में आयात करने वाले देश में उत्पादित होने वाले उत्पादों की जगह ले लेता है। व्यापार सृजन आयातक देश के लिए कल्याणकारी सुधार से जुड़ा है क्योंकि यह आयातित वस्तु की लागत को कम कर देता है।

व्युत्पन्न माँग — व्युत्पन्न माँग उत्पादन के किसी उपादान (इस मामले में श्रम) की ऐसी माँग होती है जो किसी अन्य अंतिम वस्तु या माल की माँग के कारण पैदा होती है।

संयुक्त देयता ऋण

संयुक्त देयता ऋण (JLL) बैंकों द्वारा क्रमिक आधार पर लोगों के समूह को दिए गए ऋण को इंगित करता है। संयुक्त देयता का अभिलक्षण यह सुनिश्चित कर देता है कि समूह के किसी सदस्य द्वारा बाकीदारी की स्थिति में पूरा समूह ही चुकौती के लिए उत्तरदायी होगा।

संयोजक सामाजिक पूँजी

यह गरीब व्यक्तियों और प्रभावशाली लोगों के बीच अनुलंबसंबंधों को इंगित करती है।

सकल जन्म दर

यह किसी देश में आयु वितरण, उस देश में महिलाओं की आयु–विशिष्ट प्रजनन दरों और विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या के अंश का परिणाम होती है।

सकारात्मक बाह्यता

यदि किसी एक व्यक्ति के कार्यों का किसी दूसरे व्यक्ति पर उपयोगी अथवा लाभकारी प्रभाव पड़ता हो तो इसे सकारात्मक बाह्यता कहा जाएगा।

सकारात्मक अपव्यूही मिलान

यह परिघटना संयुक्त देयता ऋण (JLL) से जुड़ी है, जहाँ सुरक्षित ऋणग्राही समूह बनाने के लिए एक साथ आने का निर्णय लेते हैं, और जोखिम वाले ऋणग्राहियों के पास शेष जोखिम वाले प्रकार के समूह बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।

सतत विकास

सतत विकास की संकल्पना संसाधनों के प्रयोग में कुशलता की बजाय न्यायपूर्णता पर अधिक जोर देती है। इसका अर्थ है कि संसाधन किसी समतावादी तरीके से ही प्रयोग किए जाने चाहिए, जो कि अधिकांश लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने वाला होगा।

समुचित कार्य

समुचित कार्य वह काम है जो पुरुषों और महिलाओं को उचित आय दिलाता है, सुरक्षित नौकरी और निरापद कार्य दशाओं की गारंटी देता है तथा कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करता है।

सहकर्मी अनुवीक्षण

यह सामूहिक ऋण देने की एक परिघटना है, जिसमें समूह के सदस्य एक दूसरे की निगरानी करते हैं और जोखिम के स्तर को कम करने के लिए ऋणग्राही को प्रभावित करते हैं।

सीमित देयता

इसका अर्थ है कि यदि किसी ऋणग्राही की परियोजना विफल हो जाती है या फिर वह दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसे ऋणों की चुकौती के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

सुप्त चयापचय प्रभाव

इस प्रभाव के अनुसार, शरीर सुप्त चयापचय के लिए कम खाता है और काम के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का अधिक

कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है।

सूचना विषमता यह एक ऐसी स्थिति को इंगित करता है जिसमें ऋणदाता ऋणग्राही की आंतरिक विशेषताओं से अनभिज्ञ होता है। सूचना विषमता से जुड़ी दो प्रकार की समस्याएँ हैं – प्रतिकूल चयन (ऋणग्राही के प्रच्छन्न प्रकार संबंधी समस्या) और आचारिक संकट (ऋणग्राही की प्रच्छन्न कार्यवाहियों संबंधी समस्या) हैं।

सूक्ष्म ऋण यह बेरोजगार या कम आय वाले उन व्यक्तियों या समूहों को प्रदान किए गए छोटे आकार के ऋणों को इंगित करता है जो औपचारिक ऋण बाजार से बाहर रह गए हों। यह ऋण मुख्य रूप से ऋणग्राहियों की कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है।

क्षमता प्रभाव किसी व्यक्ति का बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और अधिक बल उसे उन कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं जो एक कुपोषित व्यक्ति को करना कठिन या असंभव लगता हो। बेहतर पोषण प्रस्थिति वाले व्यक्ति में कम पोषण स्तर वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक कार्य करने की क्षमता होती है।

क्षेत्रीय व्यापारिक गुट ऐसे देशों का समूह जो भौगोलिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आमतौर पर किसी प्रकार की अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (PTA) में निकटता से जुड़े होते हैं।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

कलडोर, निकोलस (1957), ''ए मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,'' *द इकोनॉमिक जर्नल*, खंड 67, अंक 268, 1 दिसंबर, पृष्ठ 591–624, https://doi.org/10.2307/2227704

कैंपबेल, डी. एवं अहमद, आई. (2012), *द लेबर मार्केट इन डेवलपिंग कंट्रीज : इंट्रोडक्शन*, iSite पर उपलब्ध।

क्रुगमैन, पॉल आर., मौरिस ओब्स्टफेल्ड, मार्क जे. मेलिट्ज (2017), *इंटरनेशनल फाइनैंस : थ्योरी एंड पॉलिसी*, दसवाँ संस्करण, पियर्सन एजुकेशन लिमिटेड।

क्रुगमैन, पॉल आर., मौरिस ओब्स्टफेल्ड, मार्क जे. मेलिट्ज (2018), *इंटरनेशनल ट्रेड : थ्योरी एंड पॉलिसी*, ग्यारहवाँ संस्करण, पियर्सन एजुकेशन लिमिटेड।

चक्रवर्ती, संजय (2013), *द प्राइस ऑफ लैंड : एक्वीजीशन, कॉन्फ्लिक्ट, कन्सिक्वेन्सिज*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

चिरिको, जोआन (2013), *ग्लोबलाइजेशन : प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स*, पहला संस्करण, सेज प्रकाशन।

चौधरी, आई.आर. (2010), अंडरस्टैंडिंग द ग्रामीण मिरैकल : इनफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, पृष्ठ 66–73.

जॉर्ज रिट्जर (2011), *ग्लोबलाइजेशन : ए बेसिक टैक्स्ट*, वाइली ब्लैकवेल।

टिम्बर्ग, टी.ए. एवं सी.वी. अय्यर (1984), इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट्स इन इंडिया, *इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेन्जिज*, 33(1), 43–59.

टोडारो, एम.पी. एवं एस.सी. स्मिथ (2017), *इकॉनोमिक डेवलपमेंट*, पियर्सन एजुकेशन लिमिटेड।

टोडारो, एम.पी. एवं एस.सी. स्मिथ (2012), *इकोनॉमिक डेवलपमेंट*, दसवाँ संस्करण, पियर्सन एजुकेशन लिमिटेड।

थिरवाल, ए.पी. (1999), *ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू डेवलपिंग इकोनॉमीज*, मैकमिलन प्रेस लिमिटेड।

दासगुप्ता, पार्थ एंड रे, देवराज, (1986), ''इनइक्वलिटी एज ए डिटरमिनेंट ऑफ मैलन्यूट्रीशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट : थ्योरी,'' *इकोनॉमिक जर्नल*, रॉयल इकोनॉमिक सोसाइटी, खंड 96 (384), पृष्ठ 1011–1034, दिसंबर।

देवराज रे (1998), *डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

पिंडिक, रॉबर्ट एस., डैनियल एल. रुबिनफेल्ड एवं प्रेम एल. मेहता (2013), *माइक्रोइकॉनॉमिक्स*, सातवाँ संस्करण, पियर्सन एजुकेशन लिमिटेड।

पुली, रॉबर्ट (1989), ''मेकिंग पुअर क्रेडिटवर्थी : ए केस स्टडी ऑफ द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया'', *वर्ल्ड बैंक डिस्कशन पेपर*, 58, वाशिंगटन डीसी : द वर्ल्ड बैंक।

फेलिक्स राज, संपत मुखर्जी, मल्लीनाथ मुखर्जी, अमिताभ घोष एवं राजेंद्र एन. नाग (2011), *कंटेंपरेरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स : फ्रॉम एडम स्मिथ टू अमर्त्य सेन*, पुनर्मुद्रित।

बर्गेस, रॉबिन एवं रोहिणी पांडे (2005): ''डू रूरल बैंक्स मैटर? एविडेंस फ्रॉम द इंडियन सोशल बैंकिंग एक्सपेरिमेंट'', *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू*, खंड 95, पृष्ठ 780–95.

बनर्जी, अभिजीत वी. एवं एस्तेर डुफ्लो (2007), ''इकोनॉमिक लाइव्ज ऑफ द पुअर,'' *जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स*, 21(1): 141–168.

बसु, कौशिक (1997), एनालिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स : द लेस डेवलप्ड इकोनॉमी रिविजिटेड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) प्रेस, अध्याय 9 और 10.

भारतीय रिजर्व बैंक (2007), क्रेडिट मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रोल ऑफ सैंट्रल बैंक्स, रिपोर्ट ऑन करंसी एंड फाइनैंस, *रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया*, पृष्ठ 119–163.

महोनी, आर., डेल, पी. एवं मैकलारेन, आर. (2007), ''लैंड मार्केट्स – वाई आर दे रिक्वायर्ड एंड हाउ विल दे डेवलप?'' *इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सर्वेयर्स, आर्टिकल ऑफ द मंथ*।

मॉर्डच, जोनाथन एवं स्टुअर्ट रदरफोर्ड (2003), ''माइक्रोफाइनेंस : एनालिटिकल इश्यूज फॉर इंडिया,'' *वर्ल्ड बैंक* के लिए तैयार किया गया पृष्ठभूमि पत्र।

मुखर्जी, एस. (2013), ''कोएक्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट्स इन इंडिया – ए स्टडी ऑफ एंटरप्रेनियल चॉइसिस फॉर हाउस–बेस्ड इंडस्ट्रीज'', *रिसर्च इन एप्लाइड इकोनॉमिक्स*, खंड 5, अंक 3, पृष्ठ 37–58.

मेयर, रिचर्ड (2002), रतन लाल (सं.) में ''माइक्रोफाइनेंस, पॉवर्टी एलिविएशन एंड इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी : इम्प्लीकेशन इन इंडिया,'' *फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी*, बोका रैटन, फ्लोरिडा : सीआरसी (CRC) प्रेस।

राज, के.एन. (1970), ''ओनर्शिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड,'' *इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू*, 5(1), 1–42.

वर्धन, प्रणव एवं क्रिस्टोफर उद्री (1999), *डेवलपमेंट माइक्रोइकॉनॉमिक्स*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, अध्याय 4.

रे, डी. (1998), *डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स*, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

रे, एस. (2019), चैलेन्जिज एंड चेन्जिज इन इंडियन रूरल *क्रेडिट मार्केट : ए रिव्यू, ऐग्रिकल्चरल फाइनैंस रिव्यू*।

रोस्टो, डब्ल्यू.डब्ल्यू. (1960), *द स्टेजिज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ*, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

वर्मन, महेंद्र पी. (2005), ''इंपेक्ट ऑफ सेल्फ–हैल्प ग्रुप्स ऑन फॉर्मल बैंकिंग हैबिट्स,'' *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, खंड XL, नंबर 17, 23 अप्रैल।

शापिरो सी. एवं जे. स्टिग्लिट्ज (1984), ''इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट एज ए वर्कर डिसिप्लिन डिवाइस'', *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू* (AER)।

सरकार, अभिरूप (2007), ''डेवलपमेंट एंड और डिस्प्लेस्मेंट : लैंड एक्वीजीशन इन वेस्ट बंगाल,'' विशेष लेख, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, खंड 42, अंक 16, 21 अप्रैल, 2007.

सल्वाटोर, डोमिनिक (2013), *इंटरनेशनल इकनॉमिक्स*, ग्यारहवाँ संस्करण, वाइली, संयुक्त राज्य अमेरिका।

साइमन कुज्नेत्स (1966), *मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ : रेट, स्ट्रक्चर एंड स्प्रेड*, येल यूनिवर्सिटी प्रेस।

सियामवाला, ए.,सी. पिंथोंग, एन.पोआपोंगसाकोर्न, पी.सत्संगुआन, पी.नेट्टयारक, डब्ल्यू. मिंगमानिनकिनएवं वाई. टुपुन (1990), द थाई रूरल क्रेडिट सिस्टम : पब्लिक सब्सिडीज, प्राइवेट इनफोर्मेशन एंड सैग्मैटिड मार्केट्स, *द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू*, 4(3), 271–295.

सेन, अमर्त्य (1999), *डेवलपमेंट एज फ्रीडम*, न्यूयॉर्क : नॉफ।

स्टिग्लिट्ज, जेई एवं ए. वीस (1983), ''इनसेंटिव इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन्स : एप्लिकेशन्स टू द क्रेडिट एंड लेबर मार्केट्स'', *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू*, खंड 73, पृष्ठ 912–27.

हुसैन, अहमद एम. (2004), *प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल इकनॉमिक्स*, दूसरा संस्करण, रूटलेज, टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY